

न्यायमूर्ति एस. डी अग्रवाल और एन. के. सोढ़ी के समक्ष

एम/एस स्वदेश रबर इंडस्ट्रीज,- याचिकाकर्ता।

बनाम

सरदार सिंह और अन्य- उत्तरदाता।

पत्र पेटेंट अपील सं. 685 सन् 1993

5 जनवरी, 1994।

पत्र पेटेंट अपील, 1919- खंड X- पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम- एस.

एस. 91, 79 और 83- कुछ आधारों पर बिक्री को अलग रखने के लिए

आयुक्त को आवेदन- बिक्री तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि कलेक्टर

उच्चतम बोली स्वीकार नहीं करते- जब कलेक्टर द्वारा बिक्री अनुमोदित

होगी केवल तब धारा 91 के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है और

अन्यथा नहीं- बोली लगाने वाले को कोई अधिकार केवल इसलिए नहीं है

क्योंकि बोली लगाई गई थी- बिक्री बोली के रूप में स्वीकार नहीं की गई थी- केवल जब बिक्री पूरी हो जाती है तो धारा 91 के प्रावधान लागू होते हैं- जब तक कि कलेक्टर द्वारा उच्चतम बोली स्वीकार नहीं की जाती है, तब तक बिक्री उसके पक्ष में होगी- अन्यथा नीलामी खरीदार को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है।

अभिनिर्धारित किया गया कि खंड 91 एक व्यक्ति को कुछ आधारों पर बिक्री को अलग करने के लिए आयुक्त को आवेदन करने का अधिकार देती है। हालाँकि, सवाल यह है कि जब बोली स्वीकार नहीं की जाती है तो क्या कोई बिक्री होती है।

अधिनियम की खंड 79 में प्रावधान है कि किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री के लिए आयुक्त की मंजूरी प्राप्त होने पर, कलेक्टर इच्छित बिक्री की घोषणा जारी करेगा। अधिनियम की खंड 83 कलेक्टर को समय-समय

पर बिक्री को स्थगित करने का अधिकार देती है। तत्काल मामले में बिक्री की घोषणा के बाद, कलेक्टर ने तहसीलदार को इस विशिष्ट शर्त के साथ बिक्री करने के लिए अधिकृत किया था कि बिक्री कलेक्टर की मंजूरी के अधीन होगी।

परिणामस्वरूप, हमारे विचार में, बिक्री तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि कलेक्टर उच्चतम बोली स्वीकार नहीं करता। चूंकि बिक्री कलेक्टर की मंजूरी के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए अधिनियम की खंड 91 के लागू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कलेक्टर द्वारा अनुमोदित बिक्री के बाद ही अधिनियम की खंड 91 के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। चूंकि तत्काल मामले में बिक्री नहीं हुई है क्योंकि कलेक्टर द्वारा बोली को मंजूरी नहीं दी गई थी, इसलिए प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता संभवतः अधिनियम की खंड 91 पर जवाब नहीं दे सकते हैं। हमारी राय में, केवल बोली देकर, बोली लगाने वाले को कोई अधिकार नहीं

मिलता जब तक कि उक्त बोली कलेक्टर द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है
जो संपत्ति बेचने के लिए अधिकृत व्यक्ति है।

चूंकि तत्काल मामले में, बोली स्वीकार नहीं की गई थी, बिक्री वास्तव
में नहीं हुई थी और इसलिए अधिनियम की खंड 91 के प्रावधान बिल्कुल
भी लागू नहीं होते हैं। बोली प्रतिग्रहण करने से पहले, कलेक्टर ने इसे
प्रतिग्रहण करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह पर्याप्त विचार के लिए
नहीं था। इन परिस्थितियों में, रिट याचिकाओं में विवादित आदेश कानून
में वैध थे और इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं की
गई थी भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत।

(पारस 18. 19. 20. 21 और 22)

लेटर्स पेटेंट अपील 1919—खंड X-पंजाब I और राजस्व अधिनियम-
धारा 92-क्या नीलामी में भुगतान किए गए बिक्री मूल्य की अपर्याप्तता

नीलामी बिक्री को रद्द करने के लिए वैध आधार है।

अभिनिर्धारित किया कि दोनों नीलामियों के संबंध में यह विवादित

नहीं है कि नीलामी की महत्वपूर्ण शर्तों में से एक इस प्रकार थी:

“बोलीदाता मशीनरी या पूर्ण इकाई के लिए बोली लगा

सकते हैं लेकिन बिक्री कलेक्टर की मंजूरी के अधीन होगी जो

अपने विवेक से उच्चतम बोली को प्रतिग्रहण करना करने से

इनकार कर सकता है यदि वह इसे बहुत कम समझता है।”

इस शर्त से यह स्पष्ट है कि नीलामी के लिए मांगी गई संपत्ति के संबंध

में पर्याप्त मूल्य प्राप्त किया गया है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए

बोली को मंजूरी देने से पहले कलेक्टर के लिए यह खुला था।इसलिए,

कलेक्टर द्वारा बोली को मंजूरी देने से पहले कीमत की पर्याप्तता एक

प्रासंगिक विचार था।

जिन परिस्थितियों में नीलामी के लिए मांगी गई संपत्ति का मूल्य दोनों मामलों में उच्चतम बोलियों की तुलना में बहुत अधिक था, इसलिए कलेक्टर के लिए बोली प्रतिग्रहण करने का अधिकार नहीं था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि कलेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से काम किया या भौतिक अनियमितता के साथ उच्चतम बोलीदाताओं की बोलियों को प्रतिग्रहण नहीं कर रहा है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि नीलामी में प्राप्त मूल्य की अपर्याप्तता नीलामी की कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक वैध आधार नहीं है, हमारे विचार में, कानून में कायम नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 11, 12 और 15)

वी. के. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जे. एल. मल्होत्रा,

अधिवक्ता, अपीलार्थियों के लिए।

एस. एस. दलाई, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 2 के लिए।

डी. एन. गनेरीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 के लिए।

निर्णय

एस. डी. अग्रवाल, मुख्य न्यायाधीश।

(1) दो सिविल रिट याचिकाओं सं. 2546 सन् 1988 और 5543 सन् 1988 से उत्पन्न इन चार संबंधित अपील सं. 685 सन् 1993, 656 सन् 1993, 686 सन् 1993 और 655 सन् 1993 का निपटारा ऐलपीए में पारित एक सामान्य निर्णय ऐलपीए सं. 685 सन् 1993 द्वारा किया जा रहा है। दोनों रिट याचिकाओं का निपटारा 16 जुलाई, 1993 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय द्वारा किया गया।

(2) संक्षेप में वे तथ्य, जिनके आधार पर रिट याचिकाएँ दायर की

गईं, इस प्रकार हैं:—

(3) 1988 की रिट याचिका सं. 2543 एक सुरिंदर सिंह द्वारा 10 फरवरी, 1988 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जो आयुक्त, हिसार द्वारा पारित आदेश संलग्नक पी-6 में निहित है। सुरिंदर सिंह द्वारा दी गई नीलामी को स्वीकार नहीं किया गया और नई नीलामी का निर्देश दिया गया। हिसार के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एम/एस अंजनी ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज ने हरियाणा वित्तीय निगम से ऋण लिया था। चूंकि ऋण का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए रुपये 4,98,632,86 की वसूली का प्रमाण पत्र चंडीगढ़ के कलेक्टर द्वारा हरियाणा सार्वजनिक धन (देय राशि की वसूली) अधिनियम, 1979 की खंड 3 (1) के तहत जारी किया गया था।

(4) विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विवादित संपत्ति की बिक्री के लिए मंजूरी प्राप्त की गई। विचाराधीन संपत्ति की बिक्री की उद्घोषणा 27 जनवरी, 1988 को जारी की गई थी। बेची जाने वाली संपत्ति

मेसर्स अंजनी ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज की भूमि, भवन और मशीनरी थी। 21 सितंबर, 1987 को हरियाणा वित्तीय निगम ने उस संपत्ति के मूल्य का मूल्यांकन करवाया था, जिसे रुपये 7.6 लाख में नीलाम करने की मांग की गई थी।

(5) 27 जनवरी 1988 को केवल चार व्यक्तियों ने बोली में भाग लिया। सबसे ऊंची बोली 3 लाख रुपये की थी जिसकी पेशकश सुरिंदर सिंह ने की थी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, वसूली के लिए जो प्रमाणपत्र जारी किया गया था वह रुपये 4,98,632.86, के लिए था। संपत्ति की नीलामी के बाद सुरिंदर सिंह ने नीलामी आयोजित करने वाले तहसीलदार के पास नीलामी राशि का 1/10वां हिस्सा यानी 30,000/- रुपये जमा किए। इसके बाद 10 फरवरी, 1988 को एक आदेश द्वारा, आयुक्त हिसार डिवीजन ने कलेक्टर हिसार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरिंदर सिंह की बोली स्वीकार नहीं की और नए सिरे से नीलामी का निर्देश

दिया। यह वह आदेश है जिसे 1988 की सिविल रिट याचिका सं. 2543 में चुनौती दी गई है।

(6) सरदार सिंह द्वारा 1988 की सिविल रिट याचिका सं. 2546 दायर की गई थी। यहां भी मैसर्स. स्वदेशी रबर एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हिसार में दिल्ली रोड सातरोड कलां स्थित ने हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लोन लिया था। इस पर 19,84,469,76 रुपये बकाया थे और परिणामस्वरूप उक्त राशि की वसूली के लिए कलेक्टर को एक वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। बिक्री की उद्घोषणा 12 जनवरी, 1988 को जारी की गई थी। नीलामी 20 जनवरी, 1988 को आयोजित की गई थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले सरदार सिंह थे, जिन्होंने रुपये की राशि जमा की थी। उक्त बोली के अनुसरण में नीलामी राशि का 1/4 हिस्सा 75,000/- होगा। दरअसल, जिस संपत्ति को नीलाम करने की मांग की गई थी, उसका मूल्यांकन हरियाणा वित्तीय निगम ने कराया था और उसकी

कीमत 13.25 लाख रुपये थी। लेकिन नीलामी में सबसे ऊंची बोली सिर्फ 100 रुपये की लगी. 3 लाख. 10 फरवरी, 1988 के एक आदेश द्वारा, आयुक्त, हिसार डिवीजन, ने कलेक्टर, हिसार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोली स्वीकार नहीं की और नई नीलामी का निर्देश दिया। यह आदेश दिनांक 10 फरवरी, 1988, अनुलग्नक पी-7 है, जो 1988 की रिट याचिका सं. 2546 में चुनौती का विषय है।

(7) ये दोनों रिट याचिकाएँ विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आईं, जिन्होंने उन्हें एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया।

(8) 1988 के सीडब्ल्यूपी सं. 2543 में पारित आदेश के खिलाफ, द्वारा इस न्यायालय में दो पत्र पेटेंट अपीलें दायर की गई हैं, अर्थात् 1993 की एलपीए सं. 686 मैसर्स अंजनी ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज और 1993 की एलपीए सं. 655 हरियाणा वित्तीय निगम द्वारा। इसी प्रकार 1988 के

सीडब्ल्यूपी सं. 2546 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, एलपीए सं. 685/1993 मेसर्स स्वदेशी रबर इंडस्ट्रीज द्वारा दायर किया गया है और 1993 का एलपीए सं. 656 हरियाणा वित्तीय निगम द्वारा दायर किया गया है।

(9) हमने अपीलकर्ताओं की ओर से और साथ ही उत्तरदाताओं की ओर से सभी चार अपीलों में पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है।

(10) वर्तमान अपीलों में शामिल एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या नीलामी में भुगतान की गई कीमत की अपर्याप्तता नीलामी बिक्री को रद्द करने के लिए वैध आधार हो सकती है।

(11) दोनों नीलामियों के संबंध में यह विवादित नहीं है कि नीलामी की एक महत्वपूर्ण शर्त इस प्रकार थी:--

"बोली लगाने वाले मशीनरी के लिए या पूरी इकाई के लिए बोली लगा सकते हैं, लेकिन बिक्री कलेक्टर के अनुमोदन के अधीन होगी, जो अपने विवेक से उच्चतम बोली को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है यदि वह इसे बहुत कम मानता है।"

(12) इस शर्त से, यह स्पष्ट है कि बोली को मंजूरी देने से पहले यह जांच करने के लिए कलेक्टर के पास खुला था कि जिस संपत्ति को नीलाम करने की मांग की गई थी, उसके संबंध में पर्याप्त कीमत प्राप्त हुई है या नहीं। इसलिए, कलेक्टर द्वारा बोली को मंजूरी देने से पहले कीमत की पर्याप्तता एक प्रासंगिक विचार था।

(13) कलेक्टर ने नीलामी आयोजित करने के लिए तहसीलदार को अधिकृत किया था, लेकिन बोली स्वीकार करने का अंतिम प्राधिकारी कलेक्टर था, और कलेक्टर ने विशेष रूप से नीलामी की एक शर्त बनाई थी

कि वह उच्चतम बोली को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए खुला होगा। यदि वह इसे बहुत कम समझता है।

(14) इसलिए, हमारी राय में, उच्चतम बोली लगाने वाले बिक्री के संबंध में कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि बोली स्वीकृत न हो जाए। कलेक्टर द्वारा, किसी संपत्ति को तभी बेचा गया माना जा सकता है जब कलेक्टर द्वारा उच्चतम बोली स्वीकार कर ली गई हो, उससे पहले नहीं।

(15) ऐसी परिस्थितियों में चूंकि जिस संपत्ति को नीलाम करने की मांग की गई थी, वह दोनों मामलों में उच्चतम बोली की तुलना में बहुत अधिक मूल्य की थी, यह कलेक्टर के लिए खुला था कि वह बोली को स्वीकार न करे और इस तरह यह नहीं कहा जा सकता है कि कलेक्टर ने कार्रवाई की। अवैध रूप से या अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में भौतिक

अनियमितता के साथ उच्चतम बोली लगाने वालों की बोलियां स्वीकार नहीं कर रहा है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया विचार कि नीलामी में प्राप्त मूल्य की अपर्याप्तता नीलामी की कार्यवाही को रद्द करने के लिए वैध आधार नहीं है, हमारे विचार में, कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।

(16) पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1987 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) अचल संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया निर्धारित करता है जब किसी डिफॉल्टर के खिलाफ देय राशि की वसूली के लिए कलेक्टर को वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

(17) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 91 पर भरोसा किया है और आग्रह किया है कि बिक्री को केवल कुछ सामग्री अनियमितता या प्रकाशन या संचालन में गलती के आधार पर रद्द किया

जा सकता है, न कि अपर्याप्तता के आधार पर। बताई गई कीमत.

अधिनियम की धारा 91 इस प्रकार है:--

"91. बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन.-- (1) बिक्री की तारीख से तीस दिनों के भीतर किसी भी समय, किसी महत्वपूर्ण अनियमितता या प्रकाशन में गलती के आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिए आयुक्त को आवेदन किया जा सकता है या इसका संचालन कर रहे हैं.

(2) लेकिन उस आधार पर बिक्री को रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक आयुक्त की संतुष्टि के लिए यह साबित नहीं कर देता कि उसे अनियमितता या गलती के कारण पर्याप्त चोट लगी है।

(18) उपरोक्त धारा किसी व्यक्ति को कुछ आधारों पर बिक्री को रद्द करने के लिए आयुक्त को आवेदन करने का अधिकार देती है।

हालाँकि, सवाल यह है कि जब बोली स्वीकार नहीं की जाती है तो क्या बिक्री होती है।

(19) अधिनियम की धारा 79 में प्रावधान है कि किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री के आयुक्त की मंजूरी की प्राप्ति पर, कलेक्टर इच्छित बिक्री की उद्घोषणा जारी करेगा। अधिनियम की धारा 83 कलेक्टर को समय-समय पर बिक्री स्थगित करने का अधिकार देती है।

(20) मौजूदा मामले में बिक्री की घोषणा के बाद, कलेक्टर ने तहसीलदार को इस विशिष्ट शर्त के साथ बिक्री करने के लिए अधिकृत किया था कि बिक्री कलेक्टर के अनुमोदन के अधीन होगी।

(21) परिणामस्वरूप, हमारे विचार में, बिक्री तब तक पूरी नहीं होती जब तक कलेक्टर उच्चतम बोली स्वीकार नहीं कर लेता। चूंकि कलेक्टर की मंजूरी के बिना बिक्री पूरी नहीं होती है, इसलिए अधिनियम की धारा

91 की प्रयोज्यता का सवाल ही नहीं उठता। बिक्री होने के बाद ही कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किया गया है कि अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। चूंकि मौजूदा मामले में, बिक्री नहीं हुई है क्योंकि बोली कलेक्टर द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी, इसलिए उत्तरदाताओं के विद्वान वकील संभवतः अधिनियम की धारा 91 पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारी राय में, केवल बोली देने से, बोली लगाने वाले में कोई अधिकार निहित नहीं होता है, जब तक कि उक्त बोली कलेक्टर द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, जो संपत्ति बेचने के लिए अधिकृत व्यक्ति है।

(22) चूंकि मौजूदा मामले में, बोली स्वीकार नहीं की गई थी, बिक्री वास्तव में नहीं हुई थी और इसलिए, अधिनियम की धारा 91 के प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं। बोली स्वीकार करने से पहले, कलेक्टर द्वारा इसे स्वीकार करने से इनकार करना उचित था क्योंकि यह पर्याप्त

विचार के लिए नहीं था। इन परिस्थितियों में, रिट याचिकाओं में दिए गए आदेश कानून में अमान्य थे और कला के तहत इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान की धारा 226 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

मैसर्स बॉम्बे साल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम एलजे जॉनसन, और अन्य¹, विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और [पुनर्वास](#)) अधिनियम, 1954 के तहत नीलामी द्वारा बिक्री विचार के लिए आई और इसे इस प्रकार आयोजित किया गया:—

"नियम 90(3) के तहत लगाए गए नियमों और बिक्री की शर्तों और बिक्री के नोटिस में निर्धारित से यह स्पष्ट है कि यह घोषणा कि कोई व्यक्ति नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाला था, पूरी बिक्री और हस्तांतरण

¹(1) एएक्सआर 1958 एससी 289

के बराबर नहीं है उसे संपत्ति का अधिकार: तथ्य यह है कि बोली को निपटान आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि जब तक आयुक्त ऐसी मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है, तब तक नीलामी-खरीदार के पास कोई अधिकार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां तक कि निपटान आयुक्त द्वारा बोली की मंजूरी संपत्ति के हस्तांतरण के समान नहीं है क्योंकि क्रेता को अभी तक खरीद-धन की शेष राशि का भुगतान नहीं करना है और नियम यह प्रदान करते हैं कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसके पास संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। सही स्थिति यह है कि निपटान आयुक्त द्वारा बोली के अनुमोदन पर, नीलामी-क्रेता को संपत्ति की बिक्री के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में आता है। फिर बिक्री प्रमाण पत्र के प्रावधान यह संकेत देंगे कि केवल जारी होने पर इसमें से संपत्ति का हस्तांतरण होता है।"

ऊपर दिए गए नियमों और शर्तों से यह स्पष्ट है कि यह घोषणा कि कोई व्यक्ति नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाला था, संपत्ति की पूरी बिक्री और हस्तांतरण के समान है। तथ्य यह है कि बोली को निपटान आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि जब तक आयुक्त ऐसी मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है, तब तक नीलामी-खरीदार के पास कोई अधिकार नहीं है। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि निपटान आयुक्त द्वारा बोली की मंजूरी भी संपत्ति के हस्तांतरण के बराबर नहीं है क्योंकि खरीदार को अभी तक खरीद-धन की शेष राशि का भुगतान नहीं करना है और नियम यह प्रदान करते हैं कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। हमारी राय में, यह सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू होगा। जब तक उच्चतम बोली कलेक्टर द्वारा स्वीकार नहीं की जाती, तब तक नीलामी-खरीदार को संपत्ति में कोई

अधिकार नहीं मिलता है और इसे उसके पक्ष में बिक्री नहीं माना जा सकता है।

(24) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अपीलें स्वीकार की जाती हैं; विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 16 जुलाई 1993 के आदेश को रद्द किया जाता है और दोनों रिट याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। हालाँकि, पार्टियों को पूरी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा